

# “ग्राम” से किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता को मिलेगा एक मंच- भजनलाल शर्मा

## ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम 2026) के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया

जयपुर, 10 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान मजबूत होगा तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी क्रम में जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम-2026) का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेशभर के किसानों को खेती के नवीनतम आधुनिक तरीकों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि “ग्राम” के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर रथ भेजे जाएंगे, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें। इनमें सुझाव पेटिका भी रखी जाएगी, जिससे किसान योजनाओं से जुड़े अपने सुझाव भी दे सकें।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक (ग्राम-2026) मीट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम-2026 एक ऐसा मंच होगा, जहां किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता मिलकर किसानों के सशक्तीकरण के लिए संवाद करेंगे। इस मीट के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े सेक्टर पर एकेडेमिक-संस्थागत एवं

विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ प्रदेश के किसानों को मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके

माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई थी।

इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार की

■ **ग्राम 2026 का जयपुर में 23 से 25 मई को आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में शर्मा ने ग्राम 2026 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण भी किया।**

प्राथमिकता है कि किसान पारम्परिक खेती से हटकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ें तथा खेती में नई-नई तकनीकों का उपयोग कर समृद्ध एवं खुशहाल बनें। ग्राम-2026 के माध्यम से किसानों को विश्वभर से आए कृषि विशेषज्ञों से नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी। साथ ही, वे वैश्विक मंच से भी जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में हमारी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने एवं उनके सम्मान के लिए निरन्तर कार्य कर रही है।

इस दौरान शर्मा ने ग्राम के लोगो का अनावरण एवं ब्रोशर का विमोचन किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोरामाण कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दया, मुख्य सचिव श्री. श्रीनिवास सहित, विभिन्न अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

## ‘ट्रम्प ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की ओर धकेलते रहे हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन ने ऐसे प्रस्तावों को पहले ठुकरा दिया था। ट्रंप की सरकारी संचार सेवा अनाडोलू एजेंसी (एए) ने ब्रोस्टन पब्लिक रैडियो पर दिए एक इंटरव्यू के हवाले से बताया कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रवैया बढ़े वैश्विक और आर्थिक नतीजों को जन्म दे सकता है। उन्होंने मौजूदा नाजुक सीज़फायर पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मौजूदा दो हफ़्ते के सीज़फायर पर सवाल उठाते हुए इसे बिंदू-ढाला-ढाला बताया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी, जो एक पूर्व सीनेटर भी हैं और साल 2015 में उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते में बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी।

## कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दक्षिणी राज्यों में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्टालिन और अन्य मुख्यमंत्रियों ने इस असंतुलित परिसीमन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह बड़े राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, को ज्यादा ताकत देता है और अल्प राज्यों को असहाय छोड़ देता है।

साथ ही, छोटे राज्यों ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार किया है, क्योंकि इससे उनकी भूमिका नगण्य हो जाएगी।

सितंबर 2023 में सरकार ने विपक्ष के समर्थन से एक बिल पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के आरक्षण को केवल जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है।

पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस महिलाओं के आरक्षण को लागू किया जाए और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी किया जाए। अब सरकार एक अलग और जटिलबाजी वाली रणनीति अपना रही है, जो महिलाओं के आरक्षण के बजाय, राजनीतिक और रणनीतिक लाभ पर केंद्रित है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष अब असमंजस की स्थिति में है, और वे संख्या प्रबंधन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संविधान संशोधन बिल विपक्ष के समर्थन के बिना नहीं लाया जा सकता।

# कच्चे रास्ते पर सो रहे परिवार को ट्रैलर ने कुचला

## माँ-बेटी और भांजी की मौत, तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल

■ **जिंदगी के लिए जूझ रहे बच्चों की जयपुर रैफर कर दिया गया है।**

गुदागौड़जी/झुंझुं, 10 अप्रैल (निसं)। थाना क्षेत्र जिले के नंगली दीपसिंह के समीप शुक्रवार अलसुबह ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। कच्चे रास्ते पर खुले आसमान के नीचे सो रहे एक भोपा परिवार पर अचानक मौत बनकर एक बेकाबू ट्रैलर चढ़ गया। भयावह हादसे में माँ-बेटी और भांजी की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, भोपा समाज के रामस्वरूप और रूद्रमोहा का परिवार गुरुवार शाम को ही नंगली दीपसिंह के पास एक खाली जगह पर आकर रुका था। रोजगार की तहस सभों ने वहीं डेरा डाल लिया। रात को खाना खाने के बाद बच्चे और महिलाएं जमीन पर चादर बिछाकर पहुंचाया गया, जहां प्रियंका को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सभी घायलों को झुंझुं के बीडीके अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान होटकी ने भी दम तोड़ दिया। घायलों में चार बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रैफर

में थे, तभी सुबह करीब चार बजे एक तेज रफ्तार ट्रैलर कच्चे रास्ते पर बेकाबू हो गया और सो रहे परिवार के ऊपर चढ़ गया, जिससे होटकी और उसके साथ सो रहे बच्चे बुटी तरह कुचल गए, जबकि अनिल बच गया। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत दौड़कर घायलों को संभाला। इस भयावह हादसे में होटकी की 13 वर्षीय बेटी पायल उर्फ मोडी की मौत पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को तुरंत गुदागौड़जी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रियंका को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सभी घायलों को झुंझुं के बीडीके अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान होटकी ने भी दम तोड़ दिया। घायलों में चार बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रैफर

किया गया है, जबकि रविना का इलाज झुंझुं के राजकीय बीडीके अस्पताल में चल रहा है। हादसे के तुरंत बाद गुस्सा परिजनों और ग्रामीणों ने ट्रैलर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

बताया जा रहा है कि चालक ने अपने परिजनों को फोन कर बुलाया, जिनकी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पंडित परिवार का आरोप है कि चालक के परिजन घायलों को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद शुक्रवार सुबह जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए गुदागौड़जी पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने थोड़की चौराहे पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे गुदागौड़जी थानाधिकारी सीआई सुरेश रोलान ने समझाइश कर लोगों को शांत किया और जाम खुलवाया। सीआई ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि ट्रैलर को जवाब का भरोसा दिया है और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी।

# पाक रक्षा मंत्री ने इजरायल को “शैतान” और “मानवता के लिए अभिशाप” बताया

## पर, इजरायल के प्र.मंत्री नेतन्याहू की घुड़की के बाद यह पोस्ट डिलीट की

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खजाजा आसिफ ने गुरुवार को अभूतपूर्व रूप से भड़काऊ काम किया, उन्होंने इजरायल को “दुष्ट” और “मानवता के लिए अभिशाप” कहा, क्योंकि उसने यूएस-ईरान युद्धविराम के बीच लेबनान पर हमला किया। इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी नाराजगी जताई।

आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट, जिसे अब डिलीट कर दिया है, में दावा किया कि “इस्लामाबाद में शांति वाला चल रही है, लेकिन लेबनान में नरसंहार जारी है।”

उन्होंने लिखा, “इजरायल निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान, रक्तपात बिना रुके जारी है।”

आसिफ ने अगे कहा, “मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने यूरोपीय यहूदियों को हटाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर यह कैसर

■ **खजाजा आसिफ ने इजरायल की तुलना कैसर से की और कहा, इजरायल सिर्फ लड़ाई चाहता है। उनका इशारा समझौता वार्ता के बीच में इजरायल द्वारा लेबनान पर हमला करने के संदर्भ में था।**

■ **नेतन्याहू ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कहा, इजरायल को “कैसर” बताने का अर्थ है, वे इजरायल का खात्मा करना चाहते हैं और जो इजरायल का विनाश चाहते हैं, हम उनसे लड़ेंगे।**

जैसा राज्य बनाया, वे नरक में जलें।” नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजरायल को नष्ट करने का आ आ “असहनी” है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “यह कोई ऐसा बयान नहीं है, जिसे कोई सरकार सहन कर सके, खासकर उस सरकार की तरफ से, जो शांति के लिए दृढ़ संकल्प मध्यस्थ होने का दावा करती है।”

इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने भी पाकिस्तान के नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से निंदा की, यह दर्शाते

ले रहा है। इस बीच, नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि “लेबनान के साथ “जितनी जल्दी संभव हो, सीधे वार्ता” करने का आदेश दिया है। यह कदम तब आया है, जब यूएस, इजरायल और ईरान के बीच दो सप्ताह के नाजुक युद्धविराम पर खतरा मंडरा रहा है, विशेषकर इजरायल के लेबनान में सैन्य अभियान की तेजी के बाद।

उनके कार्यालय ने बयान में कहा, “लेबनान की बाह-बाह की मांग के मद्देनजर कि इजरायल के साथ सीधे वार्ता खोली जाए, मैंने कल कैबिनेट को निर्देश दिया कि जितनी जल्दी संभव हो, लेबनान के साथ सीधे वार्ता शुरू की जाए।”

बयान में आगे कहा गया, “वार्ता का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह को निरस्त करना और इजरायल और लेबनान के बीच शांति संबंध स्थापित करना होगा। इजरायल आज लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा बेरुत को निरस्त्रीकरण करने के आ आ की सराहना करता है।”

# हुमायूँ कबीर के वीडियो के बाद औवैसी ने तोड़ा गठबंधन

## औवैसी ने कहा, उनकी पार्टी ऐसी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लग जाए

—श्रीरंज झा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। चुनाव से कुछ दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में उस समय हलचल पैदा कर दी, जब उसने एक स्टिंग वीडियो जारी किया। वीडियो में आम जनता उग्रवर्ण पार्टी (एजेयूपी) नेता हुमायूँ कबीर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ अपने संपर्क के बारे में बात करते दिख रहे हैं। वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है और कबीर ने इसे एआई जनित बताते हुए खारिज कर दिया है।

वीडियो में यह बातचीत है कि कबीर को मुसलमान मतदाताओं को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए प्रभावित करने के लिए पैसा मिलेगा।

तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी के खिलाफ कोई सीधे आरोप नहीं लगाए। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, टीएमसी भाजपा को इसमें घसीट लायी और कहा कि यह कदम एक बड़ी राजनीतिक योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। गैर-टीएमसी पार्टियों ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह वीडियो ऐसे समय पर जारी किया गया, जब चुनावों से पहले यह लोगों का अधिक ध्यान खींचेगा।

इस राजनीतिक नाटक के बाद, असदुद्दीन औवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूँ कबीर को “आम जनता उग्रवर्ण पार्टी (एजेयूपी)” के साथ गठबंधन तोड़ दिया। दोनों नेता

■ **तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो जिसमें हुमायूँ कबीर को भाजपा नेताओं के साथ तृणमूल के खिलाफ साजिश रचते हुए दिखाया गया है, को हुमायूँ ने “एआई निर्मित” कहकर खारिज कर दिया।**

■ **तृणमूल छोड़ने के बाद, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का आह्वान कर हुमायूँ कबीर ने मुसलमानों में पैठ बना ली थी, पर, इस वीडियो से उनकी छवि बिगड़ी है और इससे तृणमूल को फायदा होने की उम्मीद है।**

मुसलमान वोट बैंक को मजबूत करने के विचार से एक साथ काम मिलकर कर रहे थे, ताकि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। एआईएमआईएम ने ऑनलाइन पोस्ट में कहा, “हुमायूँ कबीर के खुलासे दिखाते हैं कि बंगाल के मुसलमान कितने संवेदनशील हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से जुड़ी नहीं रह सकती, जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठता हो। आज एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया है।”

एआईएमआईएम ने आगे कहा कि वह बंगाल में स्वतंत्र राजनीतिक आवाज के लिए एकल स्तर पर काम करेगा। यह घोषणा उस दिन की गई, जब औवैसी कबीर की पार्टी के साथ बीरभूम, आसनसोल और कोलकाता सहित जिलों में संयुक्त अभियान शुरू करने वाले थे। इस घटनाक्रम से मुसलमान बहुल

जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना में टीएमसी की संभावनाएँ मजबूत हो सकती हैं।

कबीर, जो पूर्व में टीएमसी विधायक रह चुके हैं, ने मध्य बंगाल, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में लोकप्रियता हासिल कर ली है, खासकर बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद बनाने के अपने आ आ के बाद। कबीर ने पिछले साल दिसम्बर में टीएमसी से निष्कासित होने के बाद अपनी पार्टी बनाई। कबीर अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्यायकारक आरोप लगाते रहे हैं।

## जस्टिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, न कि मोर्चे से। जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी।

# सीज़फायर दो पार्टियों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाना चाहिए, कब तक टिकेगा। तीसरा, संघर्ष का प्रॉक्सि के माध्यम से फैलाव, विशेषकर लेबनान और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में, यह इजरायल के अभियान व्यापक थिएटर को भड़काने का जोखिम उठाता है। इनमें से प्रत्येक आपस में जुड़ा हुआ है, और ये मिनिकर ये संकट के अगले चरण को परिभाषित करते हैं।

होर्मुज़ स्ट्रेट अब भी सबसे महत्वपूर्ण लीवर बना हुआ है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा इस संकरे मार्ग से गुजरता है, जिससे यह आर्थिक रक्तवाहिनी है, साथ ही धर्मनिरपेक्ष और रणनीतिक जाम के बिंदु, दोनों के रूप में काम करता है। ईरान के नियंत्रित व्यवधान ने सिर्फ कुछ देशों के जहाजों को पारगमन की अनुमति दी है और उसने स्ट्रेट बंद करने की क्षमता का संकेत भी दिया है। ईरान ने पहले ही दिखा दिया है कि असमानता पारंपरिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। पुरी तरह से अच्युत होने पर भी, केवल अनिश्चितता ने शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और ऊर्जा कीमतों को बढ़ा दिया है। भारत जैसे आयातक देशों के लिए, जोखिम केवल उच्च तेल बिल नहीं है, बल्कि वह अस्थिरता है, जो वित्तीय

योजना और मुद्रास्फीति प्रबंधन को जटिल बनाती है। सप्ताहों के बढ़ते तनाव के बाद प्रबंधित युद्धविराम अस्थायी शांति के अलावा कोई अधिक राहत नहीं देता। यह मुख्य विवादों को संबोधित नहीं करता: ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, अमेरिका-इजरायल सुरक्षा समीकरण, और विभिन्न संगठनों के माध्यम से तेहरान का क्षेत्रीय प्रभाव। वास्तव में, यह विराम सभी पक्षों को पुनर्गठित होने का अवसर देता है। वाशिंगटन अपनी निवारक क्षमता की सीमाओं का मूल्यांकन कर सकता है; तेहरान दबाव के लचीलेपन का परीक्षण कर सकता है, बिना उस सीमा को पार किए, जो भारी प्रतिशोध को आमंत्रित करे। यह क्लासिक ब्रिकमैनिशप है, जहाँ संयम सामरिक है, परिवर्तनकारी नहीं।

अधिक चिंताजनक बात यह है कि संघर्ष क्षेत्र में फैल रहा है। लेबनान में इजरायल के लगातार हमले और ईरान समर्थित समूहों की लगातार गतिविधियाँ यह संकेत देती हैं कि युद्धक्षेत्र छोटा नहीं हुआ, बल्कि स्थानांतरित हुआ है। ऐसे प्रॉक्सि टकराव संभावित इनकार की अनुमति देते हैं जबकि दबाव भी बनाए रखते हैं। फिर भी, ये गलत आकलन का जोखिम

बढ़ाते हैं। एक उच्च-हानि वाला हमला या गलत संकेत युद्धविराम को तोड़ सकता है और व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है, जिसमें कई अभिनेता प्रतिस्पर्धी लाल रेखाओं के साथ शामिल हो सकते हैं।

आर्थिक परिणाम पहले ही दिखाई देने लगे हैं। तेल बाजारों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन द्वितीयक प्रभाव अधिक दीर्घकालिक साबित हो सकते हैं। शिपिंग मार्गों में व्यवधान न केवल ऊर्जा, बल्कि रसायन, उर्वरक और मैनुफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण इनपुट को प्रभावित करता है। आपूर्ति श्रृंखलाएँ, जो पहले के झटकों से उबर ही रही हैं, फिर से तनाव का सामना कर रही हैं। वित्तीय बाजार, इस बीच, पू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को शामिल कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकद पूंजी की स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, इसका अर्थ मुद्रा दबाव और आयातित महंगाई होता है—एक असुविधाजनक मिश्रण, जब विकास अभी भी असमान है।

एक रणनीतिक सबक भी सामने आ रहा है। यह संघर्ष गहन राजनीतिक विवादों को हल करने में सैन्य श्रेष्ठता की सीमाओं को रेखांकित करता है। सटीक हमले और तकनीकी प्रभुत्व क्षमताओं

को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को समाप्त नहीं कर सकते। भूगोल, प्रॉक्सि और आर्थिक जाम बिंदुओं का उपयोग करने की ईरान की क्षमता आधुनिक संघर्ष में व्यापक बदलाव को उजागर करती है, जहाँ प्रभाव नेटवर्क के माध्यम से लागू होता है, न कि मोर्चे से।

भारत के लिए, प्रभाव तत्कालिक है और इसकी कई परतें हैं। ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी सुरक्षा, और खाने के माध्यम से व्यापार मार्ग, सभी परतें उजागर हो गई हैं। कूटनीतिक संतुलन, एक साथ अमेरिका, इजरायल और ईरान के साथ संबंध बनाए रखना, में नयी कुशलता की आवश्यकता होगी। यह संकट भारत के ऊर्जा स्रोतों को विविधीकृत करने और रणनीतिक भंडार को मजबूत करने के प्रयासों को भी तेज कर सकता है।

अंत में, वर्तमान समय समाधान के बजाय पुनःसमायोजन के बारे में है। बंदूकें अस्थायी रूप से शांत हो सकती हैं, लेकिन मूल प्रतिस्पर्धा अब भी अनुसुलझी है। आगे जो आने वाला है, वह स्थिरता की वापसी नहीं है, बल्कि अधिक जटिल संतुलन है, जहाँ तनाव प्रबंधित किया जाता है, मिट्टया नहीं जाती, और अगली वृद्धि घोषित उद्देश्य से नाहीं, बल्कि संचित धर्मण से उत्पन्न हो सकती है।

# प्र.मंत्री मोदी और ममता बनर्जी में तेज हुआ “फिश वॉर”

## प्र.मंत्री मोदी ने कहा, ममता बनर्जी की गलत नीतियों के कारण बंगाली लोगों को अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी भिदनापुर में एक सभा में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार मछली पालन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में विफल रही है, जबकि राज्य में इसकी भारी मांग है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी से पूछा कि पिछले 15 वर्षों में यह क्या कर रही थी, क्योंकि मछली की अत्यधिक मांग वाले

■ **प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन के भारी अवसर हैं, फिर भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है।**

■ **ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को अपडेट रखना चाहिए, हम पहले आंध्र से मछली मंगाते थे, पर, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती।**

इस राज्य को इसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से मछली लानी पड़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना का जवाब देते हुए, बनर्जी ने

■ **प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन के भारी अवसर हैं, फिर भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है।**

■ **ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को अपडेट रखना चाहिए, हम पहले आंध्र से मछली मंगाते थे, पर, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती।**

नॉर्थ 24 परगना में एक रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बंगाल पहले आंध्र प्रदेश से मछली आयात करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं

होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को अपडेट रखें।

बनर्जी ने कहा, “मैंने सुना कि आज उन्होंने कहा कि बंगाल में मछली का उत्पादन नहीं होता, जबकि बिहार ज्यादा उत्पादन कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। लेकिन आप बिहार में लोगों को मछली खाने की अनुमति नहीं देते। यहाँ हम बाजार से मछली खरीदकर खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा, “पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग और सी फूड उत्पादन के मामले में बहुत बड़े अवसर हैं, यहाँ मछली की

मांग के बावजूद, राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है।” उन्होंने इस जनसभा के एक वीडियो में कहा, “आज भी बंगाल को परेल्डू मांग पूरी करने के लिए अन्य राज्यों से मछली आयात करनी पड़ती है। सप्ता में 15 साल रहने के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस आपके मछली जैसी बुनियादी चीज भी उपलब्ध कराने में विफल रही, वह भी राज्य के बाहर से लानी पड़ती है।”

प्रधानमंत्री ने इस स्थिति के लिए ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और कहा, “यह तुमहारी की भ्रामक नीतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। पिछले 11 वर्षों में भारत का कुल मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।

भारत का सी फूड निर्यात दोगुना हो गया है। फिर भी, बंगाल में केवल तृणमूल सरकार की वजह से, जो उपलब्ध देश के बाकी हिस्सों में हासिल की गई, वह यहाँ नहीं हो पायी।”

रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भाजपा विधायकसभा चुनाव जीतती है तो बंगाल के लिए छह गारंटीयाँ दी जाएंगी। उन्होंने “क्रूर” तृणमूल सरकार को हटाने की मांग की तथा उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह “विकास की नई विफलताओं के मानक बना रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है।”

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और यूए एमपीए संसदकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और यूए एमपीए संसदकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और यूए एमपीए संसदकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और यूए एमपीए संसदकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और यूए एमपीए संसदकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।